

विराट भूमि

[शहडोल | बुढ़ार | धनपुरी | ब्यौहारी | जयसिंहनगर | बाणसागर]

खबर संक्षेप

3,625 रुपये का टिकट, 7,250 रुपये में पड़ा



रेलवे के चक्कर लगा- लगाकर घिसी यात्री की चप्पलें

शहडोल। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया का दिंडेरा पीटते नहीं थकती, लेकिन शहडोल रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाइए तो डिजिटल भुगतान का एक अलग ही स्मार्ट कट देखने को मिलेगा, वहां एक यात्री को टिकट तो एक ही मिली, लेकिन रेलवे के काउंटर और सिस्टम की मेहरबानी से पैसे दो बार कट गए। अब महीना बीत जाने के बाद भी रिफंड का अला-पता नहीं है और यात्री रेलवे की डिजिटल ठगी का शिकार होकर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मामला शहडोल निवासी अमित गुप्ता का है, जिन्होंने 25 जून 2026 को आरक्षण काउंटर पर यूपीआई से 3,625 रुपये का भुगतान किया। जैसे ही पैसे कटे, काउंटर का कंप्यूटर बाबा मोक्ष में चले गए और टिकट जनरेट नहीं हुआ। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने बड़ी सादगी से ज्ञान दिया कि चिंता मत कीजिए, पैसे 48 घंटे में अपने आप खाते में लौट आएंगे, आप दोबारा पेमेंट कीजिए, यात्री ने सिस्टम पर भरोसा करके फिर से 3,625 रुपये कटा दिया और टिकट हाथ में आ गई।

अब उस बात को एक महीने से अधिक बीत चुका है, लेकिन रेलवे की 48 घंटे वाली घड़ी चालू ही नहीं हुई, पीड़ित अमित गुप्ता रिफंड की आस में 8 बार शहडोल स्टेशन पर मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक और स्टेशन प्रबंधक के सामने माथा टेक चुके हैं। हर बार अफसर स्क्रीनशॉट मांगते हैं, सांचना की घुंटी पिलाते हैं और कल आना कहकर टाल देते हैं। 24 जुलाई को लिखित आवेदन दिए जाने के बाद भी फाइल दीली की दीली है। तकनीकी खराबी रेलवे की, लापरवाही कर्मचारियों की, लेकिन भुगतान आम नागरिक? क्या रेलवे प्रशासन यात्रियों के जेब पर इस तरह डाका डालकर अपनी जेबें भरना चाहता है? यदि आम जनता पर कोई बकाया हो तो रेलवे तुरंत जुर्माना ठोक देना है, लेकिन जब अपना पैसा लौटाने की बारी आती है, तो अफसर कुंमकर्णी नौद सो जाते हैं।

7 अगस्त से जिले में चलेगा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान

शहडोल। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिले में भी 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने तथा उन्हें वांछित सेवाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को जिला स्तर के अधिकारी क्षेत्रीय स्तरण कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई तथा लोक सेवा गारंटी के संबंधित प्रकरणों के निराकरण, शासन द्वारा संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं के संबंधित प्रकरणों का विन्यास कर उनका निराकरण करने, अनिवारित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा तथा अतिक्रमण से संबंधित एवं रास्ता रोकने जैसी समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त फारमर आईडी बनाने, आयुष्मान कार्ड, ई-कैम्पेयसी, आधार कार्ड बनाने स्कूली विद्यार्थियों के अपार आईडी बनाने, एमओयू का अपडेशन करने, विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने से संबंधित आवेदन प्राप्त कर लोक सेवा गारण्टी के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल से जल की उपलब्धता खाद, बीज, राशन के वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सड़कों एवं पुल-पुलियों का निरीक्षण कर मरम्मत का कार्य कराएंगे।

बनकर फूट पड़ा। शहडोल। प्रदेश में कानून व्यवस्था की अजब-गजब माया है, जब तक पीड़ित पक्ष किसी शव को सड़क के बीचों-बीच रखकर चक्का जाम न कर दे, तब तक खाकी वर्दीधारियों को साक्ष्य और तथ्य नजर ही नहीं आते। ऐसा ही एक हाई-वोल्टेज ड्रामा जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक मामूम युवती की संदिग्ध आत्महत्या के बाद परिजनों का गुस्सा बारूद बनकर फूट पड़ा।

मामला ब्यौहारी क्षेत्र के एक गांव का है, जहां युवती ने अपने ही घर में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बेटी की मौत के बाद बेबस परिजनों ने गांव के ही एक मनचले और सिर्फिने युवक पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शुरुआत में जब पुलिस का सुस्त ढरां नजर आया, तो परिजनों का सब्र टूट गया।



उन्होंने सड़क पर बेटी की लाश रखकर ऐसा उग्र प्रदर्शन शुरू किया कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने युवती का शव सड़क पर धर दिया और न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। लगभग दो घंटे तक मुख्य मार्ग पर आवामगम पूरी तरह ठप रहा। गाडियों की लंबी कतारें लग गईं और प्रशासनिक

अमले में हड़कंप मच गया। जब अफसरों को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, तब जाकर ब्यौहारी थाना प्रभारी जिया उल हक अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर दौड़े-दौड़े पहुंचे। दो घंटे तक चली कड़ी मिन्नत-मन्नतों और सख्त कार्रवाई के भरोसे के बाद कहीं जाकर परिजन शांत हुए और सड़क से शव हटाने को तैयार हुए। जैसे ही सड़क का रास्ता साफ हुआ, पुलिस का अनुसंधान अचानक सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगा, मर्ग जांच, घटनास्थल के साक्ष्यों और परिजनों के रोते-बिलखते बयानों के आधार पर पुलिस ने आनन-फानन में आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत अपराध कायम कर लिया।

जिले भर में पटवारियों की ऐतिहासिक कलमबंद हड़ताल

तहसील दफ्तरों में लटके ताले, कैडर रिव्यू और सम्मान की जंग में आर-पार के मूड में पटवारी संघ



मेहनत करने वाला पटवारी संवर्ग लंबे समय से प्रशासनिक विसंगतियों का शिकार है। पटवारी संघ की प्रमुख मांगों में शामिल हैं। समयमान वेतनमान और न्यायसंगत पदोन्नति का लाभ तुरंत दिया जाए। नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति हेतु पारदर्शी विभागीय परीक्षा का आयोजन हो। फील्ड में काम के दौरान आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और एकतरफा कार्रवाइयों से बचाने के लिए जज प्रोटेक्शन एक्ट की तर्ज पर पटवारियों को सुरक्षा दी जाए। सभी संबंधित वितीय भुगतानों का अविलंब निराकरण किया जाए। संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के नियम-विरुद्ध किए गए स्थानांतरणों को तत्काल निरस्त किया जाए। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यह लड़ाई केवल वेतन या सुविधाओं की नहीं है, बल्कि यह पटवारी पद की गरिमा, न्याय

और सुरक्षित कार्य-वातावरण को सुनिश्चित करने की लड़ाई है। जब तक सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेते हुए लिखित आदेश जारी नहीं करती, तब तक कलम की स्याही नहीं चलेगी।

जनहित के प्रति संवेदनशील पटवारी

हड़ताल के कारण तहसीलों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा सुधार, रिकॉर्ड अपडेट, फसल गिरादवरी, फार्मर रजिस्ट्री और आय-जाति-निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन जैसे तमाम महत्वपूर्ण राजस्व कार्य ठप पड़े हैं। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों और गांवों से किराया फूंककर तहसील पहुंचने वाले किसानों और आम नागरिकों को दफ्तरी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हालांकि,

आंदोलनकारी पटवारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि आम जनता को हो रही इस असुविधा के लिए पटवारी नहीं, बल्कि शासन की वर्षों पुरानी हठधर्मिता और उदासीनता जिम्मेदार है। पटवारी स्वयं ग्रामीण जनता और किसानों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं और चाहते हैं कि सरकार अविलंब संघ के प्रांतीय प्रतिनिधियों के साथ मेज पर बैठकर सकारात्मक वार्ता करे और गतिरोध को समाप्त करे। यदि सरकार समय रहते संवाद कायम कर लेती, तो आज आम जनता को परेशान नहीं होना पड़ता।

वया कुंमकर्णी नौद से जागेगी सरकार

पटवारी संघ ने उम्मीद जताई है कि जनहित, किसानों की सहूलियत और प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही संवेदनशील रुख अपनाएगी। संघ ने मांग की है कि सरकार पटवारियों के कैडर रिव्यू सहित सभी न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय ले, ताकि राजस्व तंत्र पुनः अपनी पूरी ऊर्जा, क्षमता और समर्पण के साथ जन-सेवा के कार्यों में जुट सके। अब गेंद पूरी तरह शासन के पाले में है कि वह संवाद का रास्ता चुनकर इस गतिरोध को खत्म करती है या कर्मचारियों को सड़क पर रहने पर मजबूर करती है।

आशिकी और पुरानी अदावत के चक्कर में खूनी संग्राम!

शहडोल

प्यार में दिल टूटने या तकरार होने पर लोग शायरी अर्ज करते हैं, लेकिन देवलौद के धरी गांव में इश्क का खूमार ऐसा चढ़ा कि बात सीधे ट्रैक्टर से कुचलकर जान लेने तक पहुंच गई, प्रेम-प्रसंग की पुरानी रंजिश में आपा खो चुके 20 साल के एक सिरफिरे युवक ने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए हल चलाने वाले ट्रैक्टर को ही हत्या का हथियार बना डाला। मामला देवलौद थाना क्षेत्र का है, जहां आशिकी और पुरानी अदावत के चक्कर में खूनी संग्राम छिड़ गया। आरोपी चन्द्रमणि उर्फ आकाश बैस उम्र 20 वर्ष ने दूसरे पक्ष पर ऐसा ट्रैक्टर-हमला किया कि दो लोग उसकी चपेट में आ गए। इस भीषण हादसे में रामप्रताप कोरी की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई, जबकि दुर्गा प्रसाद कोरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जो फिलहाल अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।

बैरिहाई के जंगलों से पकड़ाया कातिल ट्रैक्टर

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घातक वाहन के साथ फुर्त हो गया, लेकिन देवलौद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने पीछा करते हुए बैरिहाई के घने जंगलों से हथ्या में इस्तेमाल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और मुख्य आरोपी आकाश बैस को धर दबोचा। मामले में एक नाबालिग (विधिविरुद्ध बालक) की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस ने बीएनएस और एसपी/एसटी एक्ट की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप सिंह क अगुवाई में सड़न इन्द्रलाल पुरी, प्र.आर. दिनेश शुक्ला, आर. अभिषेक तिवारी और साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को अदालत में पेश कर दिया।

हत्या की शिकायत करने वाले पीड़ित की ही पिटाई, कोरे कागजों पर लिए अंगूठे!

शहडोल। यदि आपको लगता है कि पुलिस महकमा पीड़ितों की सुरक्षा और न्याय के लिए बना है, तो जयसिंहनगर थाने की यह खोफनाक दस्तान आपकी यह गलतफहमी मिटाते में दूर कर देगी। यहां इश्काफ की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित परि और उसके बेटे को न्याय तो नहीं मिला, लेकिन पुलिसिया डंडों की खातिरदारी,

1 लाख रुपये की अडी और गांजे के केस में फंसाए की धमकी जरूर मिल गई। पूरा मामला बाम नरगी पंचायत धियार का है, जहां रामकुमार सिंह मरावी उम्र 58 वर्ष की पत्नी फूलबाई की बीती 27 जून को अंधविश्वास (टोन्टी) की रंजिश के तहत निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। आरोप महेश सिंह गोड, बाबू सिंह, लक्ष्मण और बाबी बाई पर है। लेकिन हत्यारों पर शिकंजा कसने के बजाय जयसिंहनगर पुलिस उलट आरोपियों के हमदर्दी की भूमिका में उतर आई। जब जयसिंहनगर थाने में शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो लावार पीड़ित रामकुमार 28 जुलाई को पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। इस उरी बात जयसिंहनगर थाने में बैठे आरोपियों के रिश्तेदार पुलिसकर्मियों को नागवार गुजर, शिकायत के ऐजन में 31 जुलाई की रात पीडित रामकुमार और उसके 38 वर्षीय बेटे अशोक सिंह को थाने में बंद कर बैरहनी से पीटा गया। मारपीट



दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले के तीन मुख्य किरदारों रामखिलावन जायसवाल, आशीष जायसवाल और धरमवीर मौर्य को तो वारदात के तुरंत बाद ही धर दबोचा और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन चौथा शातिर साथी प्रमोद कुमार मौर्य वारदात के बाद ऐसा फुर्त हुआ कि पुलिस चार साल तक हवा में लाठी भांजती रही।

5 हजार का इनाम और 4 साल का इंजाज

जब साहबों की तमाम दबिशें नाकाम साबित



के दौरान दबाव बनाया गया कि वे खुद कबूल करें कि हत्या उन्होंने ही की है, इतना ही नहीं, 5 सफेद कोरे पन्नों पर अंगूठे और दस्तखत ले लिए गए। 1 लाख रुपये ऐठने की कोशिश की गई और फर्जी गांजे का केस बनाकर जेल भेजने का खोफ दिखाया गया। पुलिसिया शह मिलते ही बेवोहक हुए आरोपियों और उनकी महिला रिश्तेदार सुशीला बाई ने पीड़ितों को झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाए और गांव से बाहर निकालने की खूनी धमकियां देना शुरू कर दिया है। जालम यह है कि हत्यारों और खाकीधारियों के इस नापाक मजजुज से पीड़ित परिवार अपनी ही जान बचाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने की मजबूर है। पीडित रामकुमार ने पुनः एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञान सौंपा है और केंद्रीय गुप्तचर पुलिस निरीक्षक से निषेध जांच कराने की मांग की है।

login : www.haribhoomi.com

जयसिंह नगर की सड़क बनी तालाब!

रीवा राहडोल की बदहाल सड़क बनी मुसीबत

स्कूली बच्चों और राहगीरों की जान पर मंडरा रहा खतरा

जयसिंहनगर

लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन का यदि बस चले, तो रीवा-शहडोल स्टेट हाईवे पर जयसिंहनगर थाने के पास लगे स्वागतम बोर्ड के नीचे एक नया साइनबोर्ड टंगवा दिया जाए, आगे सड़क नहीं, जल-क्रीड़ा क्षेत्र है, अपनी नाव का इंतजाम स्वयं करें! हल्की सी फुहार पड़ती नहीं कि जयसिंहनगर नगर का यह मुख्य मार्ग अपनी मूल पहचान खोकर किसी बरसाती नाले या प्राकृतिक तालाब का रूप धारण कर लेता है। गंदे पानी का जलजमाव, ऊपर से घुटने-घुटने तक गहरे गड्ढे और उनसे उड़ता बदबूदार कीचड़। इस मार्ग की बदहाली देखकर अब तो यह शक होने लगा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग का बजट सड़कों के निर्माण के लिए आता है या क्षेत्र में गुप्त रूप से मत्स्य पालन की योजना चलाने के लिए आता है।

नौनिहालों की खतरों के खिलाड़ी वाली परीक्षा

सबसे शर्मनाक और चिंताजनक पहलू यह है कि इसी कीचड़-युक्त नौकायान केंद्र से होकर रोजाना संस्कार शिशु शिक्षा निकेतन और सेंट थॉमस स्कूल के सैकड़ों मासूम गुजरते हैं। घर से साफ-सुथरी, इस्तरी की



हुई यूनिफॉर्म पहनकर निकलने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचने से पहले ही कीचड़ से स्नान करा दिया जाता है। तेज रफ्तार से गुजरती गाड़ियों के

पहिये जैसे ही इस गंदे पानी में छपाक करते हैं, मासूमों की किताबें और कपड़े दलदल में सन जाते हैं। अधिभावक हर रोज अपने बच्चों को स्कूल

भेजते वक़्त भारी मन से प्रार्थना करते हैं कि आज उनका चिराग सही-सलामत घर लौट आए। सड़क पर गड्ढों के बीच इतना पानी भरा रहता है कि यह अंतर कर पाना असंभव है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। क्या प्रशासन बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के साथ-साथ लाइफ जैकेट भी मुफ्त बांटने की योजना बना रहा है?

प्रशासन की कुंमकर्णी नींद और जन-मुसीबत

स्थानीय नागरिक, बुजुर्ग और महिलाएं रोज इस प्रशासनिक नाकामी का दंश झेल रहे हैं। लेकिन साहबों की सेहत पर जूं तक नहीं रेंगती। थाने के ठीक बगल में स्थित इस सड़क की बदहाली यह साफ बयां करती है कि कानून के रखवालों और प्रशासनिक अमले की नाक के नीचे ही व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है। शिकायतें कागजों पर रही की तरह जमा हो रही हैं, ज़ापन दिए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने अपने कानों में रई टुंस रखी है। शायद जिले के बड़े हुकमरान किसी बड़ी त्रासदी के इंतजार में हैं। जब तक कोई मासूम किसी अनियंत्रित वाहन की चपेट में न आ जाए या गड्ढे में समाकर अपनी जान न गंवा दे, तब तक फाइलें सरकने से रहीं।

आखिर बलि किसकी ली जाएगी

नगरवासियों का गुस्सा अब फूटने की कगार पर है। जागरूक नागरिकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि समय रहते जल निकासी का स्थायी इंतजाम नहीं हुआ और गड्ढों को नहीं भरा गया, तो अगली किसी भी अप्रिय घटना की पूरी नैतिक व कानूनी जवाबदेही लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन की होगी।

सड़कें बनीं निर्माण सामग्री का गोदाम, राहगीरों की जान जोखिम में

बारिश में रेत-गिट्टी बहने से बढ़ा हादसों का खतरा, नगर पालिका की कार्रवाई पर उठे सवाल

हरिभूमि न्यूज़ कोतमा। नगर की सड़कें इन दिनों भवन निर्माण सामग्री और मलबे के अवैध कब्जे की शिकार होती जा रही हैं। शहर के कई प्रमुख मार्गों, गलियों और मोहल्लों में ईट, रेत, गिट्टी, सीमेंट और निर्माण मलबे के ढेर खुलेआम सड़क पर डाले जा रहे हैं। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम नागरिकों, राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। बारिश के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। सड़क किनारे रखा गया रेत और गिट्टी बारिश के पानी के साथ बहकर सड़क पर फैल जाता है, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं। ऐसे में दौपहिया वाहन चालकों के फिसलने, दुर्घटनाग्रस्त होने और राहगीरों के घायल होने की आशंका लगातार बनी रहती है। रात के समय बिना किसी चेतावनी संकेत के सड़क पर पड़ा निर्माण मलबा दुर्घटनाओं को न्योता देता है। निर्माण सामग्री के कारण कई स्थानों पर सड़कें संकरी हो गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। फुटपाथों पर



भी ईट, गिट्टी और सीमेंट के बोरे रख दिए जाने से पैदल चलने वाले लोगों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। वहीं खुले में

पड़े निर्माण मलबे और सामग्री से उड़ने वाली धूल आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रही है। धूल के कारण सांस संबंधी बीमारियां,

एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने की आशंका बनी रहती है। नगरवासियों का कहना है कि बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन किए सार्वजनिक सड़कों को निर्माण सामग्री ढंप करने का स्थान बना लिया गया है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका ऐसे मामलों में तत्काल अभियान चलाकर सड़क पर रखी निर्माण सामग्री जन्त करे, जिम्मेदार लोगों पर जुर्माना लगाए तथा दोबारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। नागरिकों का कहना है कि भवन निर्माण करने वाले सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वे निर्माण सामग्री अपनी निजी सीमा के भीतर ही रखें। सार्वजनिक सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

50 फीट गहरे कुएं में उतरकर सांप का सफल रेस्क्यू

हरिभूमि न्यूज़ भालुआड़ा। ग्राम पंचायत ढारसागर में एक साहसिक रेस्क्यू अभियान उस समय देखने को मिला, जब करीब 50 फीट गहरे कुएं में फिंछले एक माह से फंसे एक विशालकाय सांप को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह जोखिम भरा कार्य भालुआड़ा निवासी संप्र प्रहरी संतोष कुमार गुप्ता ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरा किया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत ढारसागर निवासी देवेंद्र द्विवेदी के घर के कुएं में फिंछले एक माह से अधिक समय से एक बड़ा सांप दिखाई दे रहा था। परिवार के लोग लगातार भय के साये में जी रहे थे। उन्हें आशंका थी कि पानी निकालते समय सांप बाहर निकलकर किसी पर हमला कर सकता है। काफी प्रयासों के बावजूद सांप को सुरक्षित बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं सुझा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर संप्र प्रहरी संतोष कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे। करीब 50 फीट गहरे कुएं में उतरना अपने आप में बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्होंने रस्सी को कम्बर और हाथ में बांधकर सावधानीपूर्वक कुएं में उतरने का निर्णय लिया। काफी मशकत के बाद उन्होंने लगभग ज़ात से आठ फीट लंबे अस्तरिया संप्र को सुरक्षित पकड़कर कुएं से बाहर निकाल लिया। संतोष गुप्ता ने बताया कि लंबे समय तक कुएं में फंसे रहने के कारण संभवतः सांप को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाया था, जिससे वह काफी सुस्त हो गया था। इसी वजह से उसका सुरक्षित रेस्क्यू संभव हो सका। सांप को बाहर निकालने के बाद उसे सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया गया। संप्र के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद देवेंद्र द्विवेदी के परिवार और आसपास के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने संप्र प्रहरी संतोष कुमार गुप्ता के साहस, सुझाव और समाजसेवा की भावना की जमकर सराहना की। संप्र प्रहरी संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि कुएं में उतरकर किसी भी वन्यजीव, विशेषकर विषैले या बड़े सांप का रेस्क्यू करना बेहद कठिन और जोखिम भरा कार्य है। ऐसे अभियानों के लिए सुरक्षा किट और आवश्यक बचाव उपकरण होना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी सुरक्षा किट उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने शासन-प्रशासन से मांग की कि वन्यजीव संरक्षण और जनसेवा में लगे ऐसे स्वयंसेवियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार के रेस्क्यू अभियान और अधिक सुरक्षित ढंग से किए जा सकें।

कोतमा में निजी स्कूलों की मनमानी पर उठे सवाल

फीस, बस किराया, यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर अभिभावकों पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ

हरिभूमि न्यूज़ कोतमा।

नगर में संचालित निजी विद्यालयों द्वारा फीस, बस किराया, यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर लगातार की जा रही मनमानी वसूली अब अभिभावकों के लिए गंभीर आर्थिक और मानसिक परेशानी का कारण बनती जा रही है। अभिभावकों का आरोप है कि अधिकांश निजी स्कूल बिना किसी ठोस कारण और पर्याप्त सूचना के हर वर्ष शुल्क में भारी वृद्धि कर देते हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। नगर में निजी विद्यालयों पर प्रभावी निगरानी नहीं होने के कारण संचालक मनमाने ढंग से शुल्क निर्धारण कर रहे हैं।

अभिभावकों का कहना है कि कई स्कूल प्रत्यक्ष रूप से फीस बढ़ाने के बजाय

डेवलपमेंट फंड, वार्षिक शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, गतिविधि शुल्क, स्मार्ट क्लास शुल्क तथा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश के लिए प्रमोशन फीस जैसे अलग-अलग मदों में राशि वसूलते हैं। इससे वास्तविक फीस वृद्धि छिप जाती है और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। निजी विद्यालयों पर कम दूरी के विद्यार्थियों से भी पूरे वर्ष का या अत्यधिक मासिक बस किराया वसूलने के आरोप लग रहे हैं। वहीं ईंधन की मामूली बढ़ोतरी का हवाला देकर परिवहन शुल्क में भी भारी वृद्धि कर दी जाती है। इसके अलावा कई विद्यालय अभिभावकों को चुनिंदा दुकानों अथवा स्कूल परिसर से ही महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। कई स्थानों पर एनसीईआरटी की पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने का दबाव बनाया जाता है। नए सत्र के दौरान या उसके बाद भी शुल्क बढ़ाकर वसूली किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं।

निजी विद्यालयों की फीस अनियंत्रित करने के लिए राज्य में फीस नियामक समिति का प्रावधान है। नियमों के अनुसार समिति विद्यालयों के खातों की जांच और लेखा परीक्षण कर सकती है तथा अनियमितता मिलने पर जुर्माना लगाने से लेकर मान्यता समाप्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। इसके बावजूद अभिभावकों का आरोप है कि ऐसी कार्रवाई शायद ही कभी देखने को मिलती है। जिला शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर भी

निगरानी की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिभावकों का कहना है कि प्रभावी निरीक्षण नहीं होने से निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ रही है। यदि फीस जमा नहीं होने के कारण किसी छात्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, परीक्षा में बैठने से रोका जाता है या विद्यालय से निष्कासित किया जाता है, तो यह कानूनन गंभीर मामला हो सकता है। ऐसी स्थिति में अधिभावक राज्य अथवा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत कर सकते हैं। वहीं परिवहन या अन्य सेवाओं के लिए शुल्क लेकर निर्धारित सुविधा नहीं देने की स्थिति में उपभोक्ता आयोग का भी सहारा लिया जा सकता है। दैनियमों के अनुसार विद्यालय अधिभावकों को एकमुश्त कई महीनों अथवा पूरे वर्ष की अग्रिम फीस जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बिना उचित कारण के बार-बार यूनिफॉर्म का रंग या डिजाइन बदलना भी निजी स्कूलों से मांग की है कि कोतमा के निजी विद्यालयों में फीस, बस किराया, किताबें और यूनिफॉर्म के नाम पर हो रही कथित मनमानी की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही नियमों के अनुरूप उचित शुल्क एवं बस किराया निर्धारित कर अधिभावकों को राहत दिलाई जाए, ताकि शिक्षा के नाम पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।

दीनदयाल कॉम्प्लेक्स बना सीलन और जलभराव का कॉम्प्लेक्स

जर्जर भवन में दहशत के बीच कारोबार करने को मजबूर व्यापारी

हरिभूमि न्यूज़ कोतमा।

नगर पालिका कोतमा द्वारा लगभग दो दशक पहले करौड़ों रुपये की लागत से निर्मित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स आज अपनी बदहाल व्यवस्था और लापरवाही की कहानी बयां कर रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-3 स्थित इस व्यावसायिक परिसर में हर वर्ष बारिश शुरू होते ही जलभराव, दीवारों में सीलन, रिसाव और भवन के जर्जर होने की समस्या विकराल रूप ले लेती है। हालात ऐसे हैं कि प्रथम तल पर स्थित दुकानों में बार महीने तक व्यापार करना लगभग असंभव हो जाता है। दुकानदारों का कहना है कि कई बार दुकानों में रखा सामान भी सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

करीब 20 दुकानों वाले इस कॉम्प्लेक्स में वर्षों से जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क और नालियों का बारिश का पानी सीधे परिसर में प्रवेश कर जाता है। प्रथम तल तक पानी भर जाने से आवंटित दुकानों का उपयोग नहीं हो पाता और पूरे वर्षा काल में व्यापार प्रभावित रहता है। व्यापारियों का आरोप है कि दीनदयाल कॉम्प्लेक्स के बगल में नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान दोनों भवनों के बीच पर्याप्त सुरक्षा और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। दोनों इमारतों के बीच



बने गैप से लगातार पानी रिसता रहता है, जिससे पुरानी इमारत की दीवारों में सीलन बढ़ गई है। कई कमरों की दीवारों में छेद हो चुके हैं और प्लास्टर झड़ने लगा है, जिससे भवन की मजबूती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

लगभग 20 वर्ष पुराने इस कॉम्प्लेक्स में लगातार पानी रिसने से दीवारें कमजोर होती जा रही हैं। कई स्थानों पर दरारें और छेद दिखाई देने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत और तकनीकी जांच नहीं कराई गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय से ही जलभराव की समस्या बनी हुई थी। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने सुबह और रात के समय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर पंप के माध्यम से निश्चित जल निकासी की व्यवस्था बनाई थी। वर्तमान में ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। अब पानी भर जाने के बाद शिकायत मिलने पर

ही पंप लगाया जाता है, तब तक दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में कई दुकानों का संचालन बंद करना पड़ता है। दुकानदारों को अपना सामान दूसरी जगह रखना पड़ता है, जिससे

अतिरिक्त खर्च के साथ व्यापार भी प्रभावित होता है। उनका कहना है कि वर्षों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। व्यापारियों का कहना है कि तीन महीने पहले बस स्टैंड के समीप एक बहुमंजिला इमारत गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। उस दर्दनाक हादसे के बाद भी नगर पालिका ने दीनदयाल कॉम्प्लेक्स जैसे जर्जर भवनों का निरीक्षण तक नहीं कराया। लगातार कमजोर हो रही दीवारों और जलभराव के बीच व्यापार करने को मजबूर दुकानदार हर समय किसी अनहोनी की आशंका में जी रहे हैं। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका से मांग की है कि कॉम्प्लेक्स की तत्काल तकनीकी जांच कराई जाए, जल निकासी की स्थायी व्यवस्था बनाई जाए, दीवारों की मरम्मत कर भवन को सुरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।





ब्लाक स्तरीय कबड्डी का हुआ आयोजन

सिलौड़ी। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलौड़ी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एसएन पांडे के निर्देशन में आयोजन किया गया। आयोजन में टीमरखेड़ा ब्लॉक के संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया पान, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया पान, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसेल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिन्ना पिपरिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कछार गांव बड़ा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक सिलौंडी, शासकीय माध्यमिक शाला बरहटा एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलौंडी एवं अन्य विद्यालयों के छात्राओं ने भाग लिया । कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती पंचों संतोष बर्मन, संकुल प्राचार्य चंद कुमार परस्वर, सुभाष बागरी, रेफरी विजय कुमार हल्दकर एवं अंकित कुमार बागरी ब्लॉक खेल नोडल प्रभारी विशाल सिंह बरकड़े प्रभारी प्राचार्य आदि मौजूद रहे।

प्रभातफेरी के साथ मानस पाठ प्रारंभ

सिलौड़ी। सिलौंडी में श्री बाला जी मंदिर में 24 घंटे का श्री राघरचित मानस पाठ सुबह प्रभातफेरी और पूजन अर्चन के साथ शुरू हुआ । श्री बाला जी मंदिर से प्रभातफेरी शुरू होकर गांव के सभी मंदिरों में पूजन अर्चन किया । रत्नराम श्रीवास,जामुन बाई श्रीवास, दुर्गा प्रसाद श्रीवास ,संतोष श्रीवास ने श्री रामचरित मानस को सिर पर रखकर गांव में प्रभात फेरी निकाली। पूजन अर्चन के साथ श्री राम चरित मानस पाठ का शुभारंभ श्री बाला जी मंदिर में हुआ। इस दौरान मुकेश श्रीवास, द्वारका प्रसाद श्रीवास, अजय श्रीवास, सुशील श्रीवास, अनिकेत श्रीवास, सुमित श्रीवास, विजय तिवारी, बालमुकुंद चोबे, रमेश राय, सहित सैकड़ों भक्त लोग की मौजूदगी रही।

नाले में हो रहा अतिक्रमण जल प्रवाह हो रहा बाधित बड़वारा।

स्थानीय सार्वजनिक नाला जिसे सड़क घाट के नाम से जाना जाता है उसके ऊपर कुछ कतिपय लोगों के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है जिसकी शिकायत ग्राम की सरपंच, बड़वारा तहसीलदार से की गई है। शिकायत में बताया गया है कि बड़वारा के सड़क घाट नाला के ऊपर कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है जिससे सार्वजनिक नाला के जल प्रवाह को बाधित कर दिया गया है। जल प्रवाह रुकने से वर्षा के जल की निकासी अवरुद्ध होने से जल भराव होने से गंदगी बढ़ेगी जिससे आम नागरिकों एवम समीपस्थ रहने वाले रहवासियों को असुविधा व परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शिकायत के माध्यम से स्थानीय ग्राम पंचायत एवम राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की गई है कि सड़क घाट सार्वजनिक नाले के ऊपर किये गए अतिक्रमण की शीघ्र जांच कर कार्रवाई की जाए ताकि उक्त स्थल पर से सुचारु रूप से जल प्रवाह हो सके एवम भविष्य में किसी प्रकार की जन हानि एवम जल भराव की समस्या उत्पन्न नहीं होये पाए।

जिले में अब तक 370.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज कटनी। जिले में 1 जून से 4 अगस्त तक कुल 370.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। विदित हो कि पिछले आलोच्य अवधि के दौरान जिले में 726.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख मुन्ना लाल तिवारी ने बताया कि जिले में इस अवधि में कटनी तहसील में 373.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जबकि तहसील रीठी में 538.7 मिलीमीटर, बड़वारा तहसील में 234.5 मिलीमीटर, बरही तहसील में 215.8 मिलीमीटर और विजयराघवगढ़ तहसील में 261.4 मिलीमीटर, बहोरीचंद तहसील में कुल 337.5 मिलीमीटर एवं स्लीमनाबाद तहसील में 681.4 मिलीमीटर तथा टीमरखेड़ा तहसील में 320.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है।

विद्युत वितरण कंपनी में पदोन्नति प्रक्रिया पर भड़का आक्रोश: 52 पद रोके जाने से कनिष्ठ अभियंताओं में असंतोष, तत्काल पदोन्नति की मांग

जबलपुर। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में कनिष्ठ अभियंता (JE) से सहायक अभियंता (AE) के पद पर चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर कनिष्ठ अभियंताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों का आरोप है कि पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान लगभग 52 पदों को अनावश्यक रूप से रोक दिया गया है, जिससे कंपनी कैडर के पात्र कनिष्ठ अभियंताओं के करियर में आगे बढ़ने के अवसर छीने जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोके गए पदों में से 22 पद 'बोर्ड कैडर' के नाम पर आरक्षित रखे गए हैं,

जबकि लगभग 30 पदों को बिना किसी स्पष्ट कारण के अतिरिक्त रूप से रिक्त छोड़ दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि इन पदों को भरने के बजाय खाली रखना पदोन्नति प्रक्रिया की निष्पक्षता और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सेवानिवृत्ति के बाद तक दंड अवधि, फिर भी आरक्षित पद

कर्मचारियों ने एक मुख्य विसंगति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि बोर्ड कैडर के लिए

आरक्षित 22 पदों पर शामिल कई कर्मचारियों की विभागीय दंड (Punishment) अवधि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से भी अधिक लंबी है। ऐसे में वे कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में कभी पदोन्नति के पात्र नहीं हो सकेंगे। इसके बावजूद उनके नाम पर पदों को सालों-साल आरक्षित रखना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है।

मांगें और समाधान का सुझाव

उक्त स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों ने प्रबंधन के समक्ष प्रमुख मांगें रखी हैं:

व्यक्तिगत समीक्षा: दंड झेल रहे बोर्ड कैडर कर्मचारियों के मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा की जाए। जिन कर्मचारियों के रिटायरमेंट तक पात्र होने की कोई संभावना नहीं है, उनके स्थान पर खाली पड़े पदों पर कंपनी कैडर के योग्य कनिष्ठ अभियंताओं को तुरंत पदोन्नति दी जाए। सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर तुरंत नियुक्ति: हर महीने बोर्ड कैडर के कई सहायक अभियंता सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे नए पद लगातार खाली हो रहे हैं। इन पदों पर बिना किसी देरी के

नियमानुसार कंपनी कैडर के अभियंताओं को पदोन्नत किया जाए ताकि विभागीय काम प्रभावित न हो। पारदर्शिता और समान अवसर: प्रबंधन पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाते हुए अनावश्यक रूप से पदों को रोके रखने या आरक्षित रखने की व्यवस्था को तुरंत समाप्त करें। कनिष्ठ अभियंताओं का स्पष्ट कहना है कि यदि प्रबंधन ने उनकी न्यायसंगत मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया, तो योग्य कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

धनपुरी का विकास सड़क चौड़ीकरण पर अटका

नगरगड़ा नाला से बधिया नाला तक मॉडल रोड बनाने की मांग, जाम से परेशान जनता; रीवा—अमरकंटक मार्ग के चौड़ीकरण पर भी जोर

धनपुरी। कभी कोयला उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए पहचान रखने वाला धनपुरी आज बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर सड़क व्यवस्था को लेकर जूझ रहा है। नगर के मुख्य मार्ग नरगड़ा नाला से बधिया नाला तक सड़क चौड़ीकरण वर्षों से लंबित है, जिसके कारण प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है। अब इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय सेवा दल (भोपाल) के संयुक्त सचिव डॉ. हीरामणि सोनी ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। प्रेस विज्ञप्ति में डॉ. सोनी ने कहा कि धनपुरी के नागरिक नियमित रूप से नगर पालिका को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विकास दिखाई नहीं देता। उनका कहना है कि नगर पालिका का विकास कार्य कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गया है, जबकि पूरे नगर को



समान रूप से सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि नरगड़ा नाला से बधिया नाला तक के मार्ग को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाए। सड़क चौड़ी होने से यातायात सुगम होगा, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और बाजार क्षेत्र में लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। डॉ. सोनी ने कहा कि धनपुरी की अधिकांश कोयला खदानें बंद होने के बाद नगर की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। जो शहर कभी कोयला उत्पादन के कारण समृद्ध माना जाता था, वह अब बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का नगर बन गया है। ऐसे समय में सड़क, यातायात और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास ही धनपुरी को

नई दिशा दे सकता है। उन्होंने रीवा—अमरकंटक मार्ग के चौड़ीकरण को भी समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि यह सड़क क्षेत्र के विकास, व्यापार, पर्यटन और आवागमन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस दिशा में शीघ्र निर्णय लिया जाता है तो धनपुरी सहित पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी।डॉ. सोनी ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि धनपुरी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सड़क चौड़ीकरण और मॉडल रोड निर्माण की योजना को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाए, ताकि वर्षों से विकास की राह देख रहे नगरवासियों की उम्मीदें पूरी हो सकें।

दो कारों में भीषण मिडंत

पाली थाना अंतर्गत nh43 स्टेशन रोड तिराहा मुदरिया में आज सुबह दो कारें आपस में भीड़ गई कार चालक बाल बाल बच्चे एक वैगन आर दूसरी शिफ्ट बैगन R सवार ओमप्रकाश मिश्रा निवासी मुदरिया उम्र 50 वर्ष अपने छोटे भाई के साथ मुदरिया रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे दूसरी शिफ्ट में इमरान खान साथ में चार लोग जो की अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विकास दिखाई नहीं देता। उनका कहना है कि नगर पालिका का विकास कार्य कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गया है, जबकि पूरे नगर को

वर्षों से जमे बाबू तीरथ वर्मा को हटाए जाने की मांग

ब्यौहारी। जनपद पंचायत ब्यौहारी-मैं अंगद के पांव की तरह कुछ कर्मचारी डटे हुए हैं उनका आज तक दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हुआ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनपद से निकलने वाली जनपद मद की राशि मनपसंद बेंडरो के खाते में भेजी जाती है और फिर कमीशन छोड़कर पूरी राशि ले ली



जाती है यह खेल कई सालों से चल रहा है आए दिन बैठक होती रहती हैं जिनका बिल निकाला जाता है जनपद पंचायत में पदस्थ बाबू तीरथ वर्मा 20 सालों से जनपद पंचायत में पदस्थ हैं क्षेत्र के लोगों ने जनपद पंचायत के बाबू को अन्यत्र स्थानांतरण किये जाने की मांग की है

एक साल पहले हुआ बोर, अब तक नहीं लगी मोटर, पानी के लिए भटक रहे लोग

अमलाड़। नगर परिषद बकहो के वार्ड क्रमांक 5 स्थित टिकरी टोला में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से रहवासी परेशान हैं। क्षेत्र में पेयजल संकट के साथ सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट की समस्या भी लंबे समय से बनी हुई है। लोगों ने नगर परिषद से जल्द समाधान की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वार्ड में करीब एक वर्ष पहले नगर परिषद द्वारा बोरवेल कराया गया था, लेकिन आज तक उसमें मोटर नहीं लगाई गई। इससे बोरवेल बेकार पड़ा है और लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से रहवासियों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है।रहवासियों ने बताया कि वार्ड की कई गलियों में सड़क और नाली का निर्माण अधूरा है, जबकि पर्याप्त स्ट्रीट लाइट नहीं होने से रात के समय आवागमन में परेशानी होती है। बरसात के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है।क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से बोरवेल



में शीघ्र मोटर लगाकर पेयजल आपूर्ति शुरू करने तथा सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।लोगों का

कहना है कि समस्याओं के समाधान में लगातार हो रही देरी से आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रस्फुटन समिति शक्ति संचय अभियान के तहत क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण

नशामुक्त समाज निर्माण का दिलाया संकल्प, निकाली जागरूकता रैली

हरिभूमि न्यूज▶▶▶ स्लीमनाबाद

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक महोदय के निर्देशानुसार प्रस्फुटन समितियों के क्षमता संवर्धन एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रस्फुटन समिति शक्ति संचय अभियान अंतर्गत जनपद पंचायत रीठी के सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष श्यामा बाई, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र साहू तथा जनपद सदस्य रतीलाल चौधरी द्वारा भी भारती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रशिक्षण के दौरान नवांकुर संस्था युवा सेवरा समिति के अध्यक्ष गोवर्धन रजक ने प्रस्फुटन समितियों की सक्रियता, दस्तावेजीकरण, रएक पेड़ माँ के नामर हरियाली यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान तथा नशा मुक्त भारत



अभियान के सफल संचालन हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में परामर्शदाता अरुण तिवारी ने रस्वस्थ सबके लिए विषय पर प्रेरक व्याख्यान देते हुए जनस्वास्थ्य एवं सामुदायिक सहभागिता के महत्व को रेखांकित किया। वहीं परामर्शदाता श्री शरद दादव ने एमआईएस प्रोटल पर गतिविधियों के समयबद्ध एवं प्रभावी अपलोड की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

दिनेश पांडे ने नशा मुक्त ग्राम पंचायत की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए सभी प्रतिभागियों को नशामुक्त समाज निर्माण का संकल्प दिलाया तथा जनजागरूकता रैली का आयोजन कराया। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्यामा बाई ने ग्राम पंचायतों में अवैध रूप से संचालित शराब कारोबार के विरुद्ध जनभागीदारी से व्यापक अभियान चलाने का आह्वान किया। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र साहू

ने नशे से होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सभी समितियों से अभियान को जन-जन तक पहुँचाने की अपील की। जनपद सदस्य रतीलाल चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिकाधिक वृक्षारोपण करने तथा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा समाजहित में संचालित जनकल्याणकारी गतिविधियों की सराहना करते हुए सभी से सक्रिय

सहभागिता का आग्रह किया।

प्रशिक्षण में जनपद पंचायत क्षेत्र की समस्त सक्रिय प्रस्फुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं, परामर्शदाताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की उल्लेखनीय सहभागिता रही। प्रतिभागियों ने अपने-अपने ग्रामों में पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, सामाजिक जागरूकता एवं जनहितकारी अभियानों को प्रभावी रूप से संचालित करने का संकल्प लिया। इस दौरान अमर बहादुर यादव, सीता सोनी, मोहम्मद मुस्तकीम, महेश बर्मन, साक्षी नामदेव, सावित्री पटेल, राधवेन्द्र यादव, ओमप्रकाश अवस्थी, उमेश रजक, लालू रजक सहित अन्य सहभागी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का समापन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ब्लाक समन्वयक जगन सिंह मसराण के द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर आभार व्यक्त किया गया।

हरिभूमि न्यूज▶▶▶ कटनी



नगर निगम में आयोजित समय-सीमा बैठक में निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रशासन की कार्यगणाली का मूल्यांकन इस बात से होता है कि नागरिकों के कार्य कितनी शीघ्रता और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जा रहे हैं। प्रत्येक आवेदन किसी नागरिक की समस्या, अपेक्षा और अधिकार से जुड़ा होता है, इसलिए उसका निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता होना आवश्यक है। निगमायुक्त ने कहा कि यदि विभाग नियमित रूप से अपने कार्यों की समीक्षा और मॉनिटरिंग करेंगे तो न केवल लंबित प्रकरणों में कमी आएगी, बल्कि विकास कार्यों एवं शासकीय योजनाओं का लाभ भी समय पर

जनसुनवाई में महापौर ने लोगों की समस्याओं का किया निराकरण



हरिभूमि न्यूज▶▶▶ कटनी

नगर पालिक निगम में मंगलवार को आयोजित महापौर जनसुनवाई में शहर के विभिन्न वार्डों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं सीधे महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरि के समक्ष रखीं। जनसुनवाई के दौरान पेयजल, सड़क, नाली, स्वच्छता, अतिक्रमण, राजस्व एवं अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित आवेदनों से सुनवाई की गई। महापौर ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रकरणवार जानकारी प्राप्त की तथा समय

सीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका परिणाम भी समय पर दिखाई देना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। महापौर श्रीमती सूरि ने कहा कि जनसुनवाई नागरिकों और नगर निगम के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने शहरवासियों से प्रत्येक मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में शामिल होकर अपनी समस्याएं सीधे प्रस्तुत करने की अपील करते हुए कहा कि नगर निगम पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितकारी प्रशासन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।



खबर संक्षेप

कोतमा में प्रस्फुटन शक्ति
संचय कार्यक्रम आयोजित,
समाज विकास और
जनभागीदारी पर मंथन

कोतमा। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, विकासखंड कोतमा (जिला अनूपपुर) के तत्वावधान में मंगलवार को बीआरपी गवन, जनपद पंचायत कोतमा में प्रस्फुटन शक्ति संचय कार्यक्रम (विकासखंड स्तरीय मासिक बैठक एवं प्रशिक्षण सत्र) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के समग्र विकास, जनभागीदारी को सशक्त बनाने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन नामांकुर संस्था के प्रतिनिधि दिलीप शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत कोतमा के अध्यक्ष जीवन सिंह, उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष अभिषेक सिंह, आजीविका मिशन के रजनीश सिंह, विकासखंड समन्वयक सरोजम साकेत, नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि ओंकार सिंह, निखिल कुमार सेनी, हिरेंद्र तिवारी, महेंद्र यादव, दिलीप शुक्ला सहित परामर्शदाता रश्मि रेकवार, सरिता मिश्रा, कीर्ति राज जैन, अजय द्विवेदी, प्रस्फुटन समितियों के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में सामाजिक विकास, जनसहभागिता और आगामी गतिविधियों की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इस दौरान दिलीप शुक्ला ने मध्यप्रदेश सरकार के एक पेड़ मां के नाम नवांकुर संस्थी तथा हर एर तिरंगा जैसे अभियानों की विस्तृत जानकारी दी और इनके सफल क्रियान्वयन में जनसहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्रावण में शिवमय हुआ अमरकंटक का रामघाट
वैदिक मंत्रों की गूंज से आलोकित हुई तपोभूमि

अमरकंटक। श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक नगरी अमरकंटक का पावन रामघाट पूरी तरह शिवमय हो उठा है। नगर परिषद अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 10 स्थित माँ नर्मदा के उत्तर तट पर इन दिनों वैदिक मंत्रों की मधुर अनुगूंज, श्रीरुद्रम के नमक-चमक पाठ, महामृत्युंजय मंत्र जाप, रुद्राभिषेक, शिव पूजन, यज्ञ-हवन और सत्संग से संपूर्ण वातावरण भक्तिरस में डूबा हुआ है। श्रावण के प्रत्येक दिन यहां श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है और हर-हर महादेव के जयघोष से तपोभूमि अमरकंटक गुंजायमान हो रही है। नर्मदा परिक्रमावासी संत स्वामी पूर्ण दास महाराज (मौनी बाबा) के सान्निध्य एवं मार्गदर्शन में पूरे श्रावण मास तक विशेष शिव आराधना का महाअनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर विश्वशांति, राष्ट्र की समृद्धि, जनकल्याण, उत्तम स्वास्थ्य और



प्रकृति के संतुलन की कामना की जा रही है। स्वामी पूर्ण दास महाराज का कहना है कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सर्वोत्तम काल है, जिसमें श्रद्धा और भक्ति से किया गया जाप, तप एवं अभिषेक जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सेवा और अन्नदान की सनातन परंपरा भी निरंतर निभाई जा रही है। प्रतिदिन नर्मदा परिक्रमा वासियों, साधु-संतों तथा दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन-कौतन, विशाल मंडारा, प्रातः बालभोग, मध्याह्न महाप्रसाद, संध्या अल्पाहार और रात्रि भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति का संकल्प है कि इस पावन धाम से कोई भी श्रद्धालु भूखा वापस न लौटे। महर्षि विद्यालय, जबलपुर से आए विद्वान वैदिक बाह्यण शास्त्रोक्त विधि-विधान से नमक-चमक रुद्राभिषेक एवं अन्य वैदिक अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। पंडित नीलकंठ प्यासी, पंडित जगदीश प्यासी, पंडित नंद कुमार शर्मा, पंडित वेद प्रकाश गर्ग, पंडित मनीष दुबे, पंडित प्रंजल अग्निहोत्री, पंडित दिलीप गर्ग, पंडित सुहानी द्विवेदी, पंडित वेद कृष्ण शास्त्री और पंडित रोहित तिवारी सहित अनेक विद्वान आचार्य वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, हवन और शिव पूजन करा रहे हैं। उनके मंत्रोच्चार से पूरा रामघाट आध्यात्मिक ऊर्जा और शिवभक्ति से सरबोपर दिखाई दे रहा है। श्रावण मास के इस विशेष आयोजन ने अमरकंटक को एक बार फिर सनातन आस्था और वैदिक परंपरा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। धूप-दीप की सुगंध, हवन की पवित्र आहुति, वैदिक मंत्रों की गूंज, हर-हर महादेव के उद्घोष और अन्नदान की अखंड सेवा से रामघाट का प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान कर रहा है। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि लोककल्याण, सेवा, संस्कार और सनातन संस्कृति के संरक्षण का प्रेरक उदाहरण बनकर श्रद्धालुओं को आस्था और सेवा का संदेश दे रहा है।

प्रदेशभर में थम सकते हैं निजी बसों के पहिए

7 की मध्य रात्रि से हड़ताल का ऐलान, नई परिवहन नीति और बढ़ती परिचालन लागत के विरोध में बस संचालकों का अल्टीमेटम, मुख्यमंत्री सहित शीर्ष अधिकारियों को भेजा ज्ञापन

अनूपपुर। मध्यप्रदेश में निजी बस परिवहन व्यवस्था पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। नई परिवहन नीति, बढ़ती परिचालन लागत और लंबित परमिट संबंधी समस्याओं को लेकर प्रदेशभर के टूरिस्ट एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बस संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन अनूपपुर ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव परिवहन के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी 8 सूत्रीय मांगों पर तत्काल निर्णय नहीं लिया गया तो 7 अगस्त की रात्रि 12 बजे से पूरे मध्यप्रदेश में टूरिस्ट, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं निजी बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जाएगा। बस संचालकों का कहना है कि नई परिवहन नीति के कई प्रावधान निजी बस व्यवसाय के लिए घातक साबित हो रहे हैं। लगातार बढ़ती डीजल कीमतें, टायर, स्पेयर पार्ट्स और वाहनों के रखरखाव पर बढ़ता खर्च पहले ही कारोबार को घाटे में पहुंचा चुका है। इसके बावजूद किराए में समुचित वृद्धि नहीं रखते हुए कहा है कि 7 जुलाई के प्रस्तावित नई योजना के उन प्रावधानों को तत्काल वापस लिया जाए, जिनसे टूरिस्ट एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है।

8 सूत्रीय मांगों पर तत्काल निर्णय की मांग

बस संचालकों ने सरकार के समक्ष प्रमुख मांगें रखते हुए कहा है कि 7 जुलाई के प्रस्तावित नई योजना के उन प्रावधानों को तत्काल वापस लिया जाए, जिनसे टूरिस्ट एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है।



मैकेनिकों और अन्य कर्मचारियों की आजीविका पर भी पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के हजारों निजी बस संचालक वर्षों से यात्रियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। धार्मिक यात्राओं, शैक्षणिक भ्रमण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों सहित विभिन्न अवसरों पर निजी बसों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन वर्तमान परिवहन नीति के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।

बस संचालकों ने सरकार के समक्ष प्रमुख मांगें रखते हुए कहा है कि 7 जुलाई के प्रस्तावित नई योजना के उन प्रावधानों को तत्काल वापस लिया जाए, जिनसे टूरिस्ट एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है।

अनूपपुर, कोतमा, बिजुरी, अमरकंटक, राजेन्द्रगाम, जैतहरी

हरिभूमि 10

आयुष्मान कार्ड से लेकर यूडीआईडी शिविर तक की तैयारियों की समीक्षा

शाम 7 बजे अचानक जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर, स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा

दवा उपलब्धता और दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निर्देश

अनूपपुर। जिले के नवागत कलेक्टर रत्नाकर झा ने बुधवार शाम करीब सात बजे जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का व्यापक जायजा लिया। लगभग डेढ़ घंटे तक चले निरीक्षण में उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का भ्रमण किया, भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर उपचार व्यवस्था की जानकारी ली तथा चिकित्सकों और अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, वर्षाकाल में सर्पदंश से निपटने की तैयारियों तथा गुरुवार को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय विशेष यूडीआईडी कार्ड शिविर की व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने प्रसूति वार्ड, जनरल वार्ड, लेबर रूम, इमरजेंसी यूनिट, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर उपचार की



गुणवत्ता, डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ की नियमित विजिट, दवाओं की उपलब्धता तथा अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मरीजों की बात गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय पर उपचार मिले और किसी भी मरीज को अनिवार्यकर परेशानी का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था का भी बारीकी

से अवलोकन किया गया। कलेक्टर ने कहा कि जिला चिकित्सालय जिले की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था है, इसलिए यहां स्वच्छता, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण उपचार हर स्थिति में सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने वार्डों में नियमित सफाई, संक्रमण नियंत्रण तथा मरीजों के लिए उपचार मिले और किसी भी मरीज को अनिवार्यकर परेशानी का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था का भी बारीकी

अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं और रिक्त पदों के संबंध में शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश

दिए कि प्रत्येक पात्र मरीज का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए तथा भर्ती मरीजों को योजना का लाभ तत्काल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव किसी भी मरीज के उपचार में बाधा नहीं बनना चाहिए। अस्पताल में आयुष्मान सहायता डेस्क सक्रिय रहे और मरीजों को योजना का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने यह भी कहा कि पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अनावश्यक चक्कर न

लगवाए जाएं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने गुरुवार, 6 अगस्त को जिला चिकित्सालय स्थित स्व-सहायता भवन में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय विशेष यूडीआईडी (यूनिक डिस्पेंसिलिटी आईडी) कार्ड परीक्षण, मूल्यांकन एवं पंजीयन शिविर की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले का कोई भी पात्र दिव्यांगजन यूडीआईडी कार्ड से वंचित न रहे। शिविर में आने वाले हितग्राहियों के पंजीयन, चिकित्सकीय परीक्षण, दिव्यांगता मूल्यांकन, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, सुगम आगमन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर बलवीर रमन, एसडीएम प्राची अग्रवाल, सिविल सर्जन डॉ. एस.आर. परस्ते, मेडिकल ऑफिसर डॉ. एस.सी. राय, डॉ. प्रवीण शर्मा, डॉ. वीरेंद्र सहित जिला चिकित्सालय का चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार दिखाई देना चाहिए और प्रत्येक मरीज तथा हितग्राही को संवेदनशीलता के साथ शासन की स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

बीच सड़क में खड़े बिजली के खंभे, अधूरी 6 करोड़ की सड़क योजना पर उठे सवाल

दुर्घटनाओं का बढ़ा खतरा, भुगतान और जवाबदेही पर भी उठे प्रश्न

अमरकंटक। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आस्था का प्रमुख केंद्र अमरकंटक में करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क योजना वर्षों बाद भी अधूरी पड़ी है। भारत सरकार की हुडको वित्तपोषित आईडीएसएमटी योजना के तहत तैयार की गई इस सड़क पर आज भी बीच मार्ग में खड़े बिजली के खंभे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद न तो अधूरी सड़क पूरी कराई गई और न ही बीच सड़क में खड़े विद्युत पोल हटाए गए। जानकारी के अनुसार आईडीएसएमटी योजना के अंतर्गत शहडोल अनूपपुर मुख्य मार्ग पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाका तिराहा से पुराने स्टेट बैंक शाखा, कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन विद्यालय, रेवा पेट्रोलियम, पुलिस थाना होते हुए पाल बंगला (अध्यक्ष निवास)



तक दोहरे सीमेंट-कंक्रीट मार्ग का निर्माण कराया गया था। लेकिन सड़क का दूसरा भाग आज तक अधूरा पड़ा है। नाका तिराहा से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने तक बनने वाला मार्ग वर्षों बाद भी शुरू नहीं हो सका, जिससे पूरी परियोजना अधूरी दिखाई देती है। सबसे चिंताजनक स्थिति सड़क के बीचों-बीच खड़े तीन विद्युत खंभों की है। रे वा पेट्रोलियम, पुलिस थाना तथा विद्युत मंडल पावर हाउस के समीप होटल के

पास स्थित इन खंभों तक डिवाइडर आकर समाप्त हो जाता है। इसके बाद वाहन चालकों को अचानक दिशा बदलनी पड़ती है, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और रात के समय यह स्थान और अधिक खतरनाक हो जाता है। नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद, विद्युत विभाग और स्थानीय प्रशासन को कई बार लिखित एवं मौखिक शिकायतें दी गईं, लेकिन

वर्षों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में प्रशासनिक उदासीनता की केंकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस मामले ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। यदि आईडीएसएमटी योजना में सड़क का पूरा निर्माण स्वीकृत था तो कार्य आज तक अधूरा क्यों है? यदि निर्माण अधूरा है तो क्या ठेकेदार को पूर्ण भुगतान कर दिया गया? यदि भुगतान हो चुका है तो अधूरे कार्य और सुरक्षा संबंधी लापरवाही की जिम्मेदारी किस अधिकारी और एजेंसी की तय होगी? आखिर वर्षों से आमजन की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला लंबित क्यों है? नगरवासियों ने जिला प्रशासन, नगर परिषद, लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, अधूरी सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा कराने तथा बीच सड़क में खड़े विद्युत खंभों को तत्काल हटाकर दुर्घटनाओं की आशंका समाप्त करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में किसी बड़े हादसे की जिम्मेदारी संबंधित विभागों से नहीं टाली जा सकेगी।

कोतमा के ऑटो वर्कशॉप में हुआ हादसा

हवा भरते समय फटा एयर टैंक, युवक की दर्दनाक मौत

कोतमा। जिले के कोतमा नगर के

श्रमिक नगर बस स्टैंड स्थित एक ऑटो वर्कशॉप में बुधवार दोपहर हुए भीषण हादसे में 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वर्कशॉप में हवा भरने के दौरान अचानक एयर टैंक तेज धमाके के साथ फट गया, जिसकी चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रिंस साहू (22 वर्ष), पिता मोती साहू, श्रीमंत नगर बस स्टैंड स्थित कुष्णा ऑटो डील, मोती ऑटो वर्कशॉप एवं धुलाई सेंटर में कार्यरत थे। बुधवार करीब 12 बजे वह वर्कशॉप में एयर टैंक के माध्यम से हवा भरने से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े और पूरे वर्कशॉप परिसर में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था

कि दूर-दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। कई लोगों को पहले लगा

कि किसी स्थान पर बम फट गया है। तेज धमाका सुनते ही आसपास के दुकानदार, राहगीर और स्थानीय लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर लोगों ने देखा कि युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों और साथियों ने बिना देर किए उसे अस्पताल

पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद प्रिंस को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। अस्पताल परिसर का माहौल भी गमगीन हो गया। बताया जा रहा है कि प्रिंस साहू का विवाह कुछ ही माह पहले छाल्पा क्षेत्र में हुआ था। परिवार में नई खुशियों का आगमन हुआ था, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने उन खुशियों को मातम में बदल दिया। युवा बेटे की असमय मौत से परिजन, रिश्तेदार और परिचित गहरे सदमे में हैं। पूरे क्षेत्र में घटना को लेकर शोक और संवेदना की

माहौल बना हुआ है। घटना के बाद ऑटो गैरजो और सर्विस सेंटरों में उपयोग किए जाने वाले एयर टैंकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे उपकरणों की समय-समय पर तकनीकी जांच, परीक्षण और रखरखाव अनिवार्य होना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जानलेवा दुर्घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल एयर टैंक किन परिस्थितियों में फटा, उसमें तकनीकी खराबी थी, टैंक पुराना था या सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। संबंधित एजेंसियों द्वारा मामले की जांच किए जाने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे किसी प्रकार की लापरवाही जिम्मेदार है।

नाम सुधार सूचना
मे नीरज साहू उम्र 44 वर्ष पिता बड़ी प्रसाद साहू, निवासी-वार्ड नं.-10 ग्राम पकुरिहा थाना व तहसील-कोतमा जिला - अनूपपुर म.प्र. गण्यपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा आधार कार्ड संख्या- (आधार नं.-392219314955) है, जिसमे मेरा नाम अंग्रेजी में NIRAJ SAHU अंकित है, एवं मेरे वोटर आईडी क्रमांक-BDC57331167 में मेरा नाम अंग्रेजी में NEERAJ SAHU अंकित है। मेरा नाम बदल आई.डी. में जो नाम लिखा है वह सत्य व सही है, उक्त दोनों नाम मेरे ही नाम है अन्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मेरे वोटर आई.डी. में जो नाम लिखा हुआ है उसका नाम को आधार कार्ड में अंकित कराना चाहता हूँ जिस हेतु यह शपथपत्र निम्नांकित कर रहा हूँ।

